

प्रेस विज्ञप्ति

पाँच गाँवों को गोद लेगा हिन्दुस्तान कॉलेज

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया हिन्दुस्तान कॉलेज उन्नत भारत अभियान का केन्द्र

शारदा ग्रुप के प्रतिष्ठित संस्थान हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम शुरू करने का अवसर मिला। आईआईटी दिल्ली इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत को समृद्ध करना है। ग्रामीण विकास प्रक्रिया में परिवर्तकारी परिवर्तन लाने के लिए देश के प्रमुख संस्थानों के ज्ञान आधार और संसाधनों को लाभ उठाना है। इस योजना के तहत देश के 841 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को चयन किया गया है।

इस अवसर पर शारदा ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री वाई.के.गुप्ता, कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री प्रदीप महथा, अधिशासी निदेशक प्रो. वी. के. शर्मा ने संस्थान के निदेशक, शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राओं को इस उपलब्धी की बधाई एवं शुभकामनायें दीं।

हिन्दुस्तान कॉलेज के निदेशक डॉ. राजीव कुमार उपाध्याय ने बताया कि कॉलेज उन्नत भारत अभियान के पाँच क्षेत्रों में कार्य करेगा जो क्रमशः साधारण सुविधायें, कारीगर उद्योग और आजीविका, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती हैं।

उन्नत भारत अभियान परियोजना के समन्वयक और असिस्टेंट डीन टी.एस. एस. सुब्रामिनियन ने उल्लेख किया कि परियोजना के उद्देश्य के तहत कॉलेज के आसपास के पाँच गाँवों को अपनाया जायेगा जिससे सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करने और विकसित करने के लिए अग्रणी सर्वेक्षण कर सके और बुनियादी तकनीकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि प्रौद्योगिकियों को जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, आर्टिसन

इंडस्ट्रीज और आजीविका के क्षेत्रों में विकसित किया जायेगा जो उन्नत भारत अभियान परियोजना के दिशानिर्देशों में है जिससे ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जा सके।

साधारण सुविधायें- उन्नत भारत के इस क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत का अधिकांश हिस्सा अभी भी गांवों में रहता है और इसलिए भारत में ग्रामीण शिक्षा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। वार्षिक सर्वेक्षण की शिक्षा रिपोर्ट (एएसईआर) नामक एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्कूलों में भाग लेने वाले ग्रामीण छात्रों की संख्या बढ़ रही है लेकिन पांचवीं कक्षा में छात्रों के आधे से अधिक छात्र दूसरी कक्षा पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं और ना ही सरल गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम। हालांकि प्रयास किये जा रहे हैं, वे सही दिशा में नहीं हैं। सर्वे में इस समस्या के लिए उद्धृत कारण एक कक्षा से अधिक घेड़ छात्रों को शिक्षित करने के लिए एकल कक्षा की बढ़ती संख्या है। कुछ राज्यों में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति भी घट रही है। ये कुछ कारण हैं कि स्कूल ग्रामीण भारत को शिक्षित करने में नाकाम रहे हैं। इस योजना से छात्रों के स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। इस योजना से तकनीकी का प्रयोग करते हुये ग्रामीण शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। यह योजना स्वस्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है।

कारीगर उद्योग और आजीविका- गाँव में उत्पादन करना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की आमदनी बढ़ाना एक अति आवश्यक काम है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा जो भी काम इस कार्यक्रम के माध्यम से लिए जायेंगे उनका स्वरूप उद्योग एवं रोजगार का ही होगा। गाँव की उपज का एक बड़ा भाग गाँव में ही संसोधित कर मूल्य वर्धन किया जाये ताकि किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त हों। लोगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी तो वे अपनी सुख सुविधाओं के लिए व्यय भी कर सकेंगे जिससे गाँव का आर्थिक तंत्र सुदृढ़ होगा, गतिशील होगा, राजस्व बढ़ेगा और कार्यक्रम अपने पैरों पे खयं खड़े होने की तरफ अग्रसित होगा।

जल प्रबंधन- जल संसाधन प्रबंधन जल संसाधनों इष्टतम उपयोग की योजना, विकास, वितरण और प्रबंधन की गतिविधि है। यह जल चक्र प्रबंधन का एक उप-ऐट है। आदर्श रूप से, जल संसाधन प्रबंधन योजना पानी के लिए सभी प्रतिस्पर्धी मांगों का सम्मान करती है और सभी उपयोगों और मांगों को पूरा करने के लिए

समान आधार पर पानी आवंटित करने की मांग करती है। पृथ्वी पर जल संसाधनों में से केवल तीन प्रतिशत ताजा है और दो-तिहाई ताजे पानी को बर्फ के ढक्कन और हिमनदों में बंद कर दिया जाता है। जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पानी दुर्लभ हो रहा है और स्वच्छ, सुरक्षित, पीने का पानी पहुंचने के लिए देशों में सीमित है। अनेक ऐसी बीमारियाँ हैं जो अशुद्ध जल के कारण फैलती हैं इस योजना के प्रारम्भ होने पर इनमें बड़ी कमी आयेगी और पुनः दवाईयों एवं अस्पतालों पर होने वाले खर्चों में कमी आयेगी। कृषि सिंचाई की विश्वसनीय व्यवस्था होने से खेती की पैदावार बढ़ेगी और एक बड़ा आर्थिक लाभ किसानों को होगा। साथ में गांवों में गंदे पानी की निकासी एवं जलोपचार से पुनः बीमारियाँ फैलने से रुकेंगी एवं पानी को सिंचाई आदि के लिए पुनर्चक्रण किया जा सकता है और ताजा जल की मांग में कमी आयेगी इससे भी एक बड़ा आर्थिक लाभ होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा- वैकल्पिक ऊर्जा खोतों के उपयोग के द्वारा हर घर और हर खेत, हर ग्राम उद्योग आदि के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता की व्यवस्था की जाएगी। सौर ऊर्जा, बायोगैस, उच्चत चूल्हे, माइक्रोहैडल, पशु एवं मानव ऊर्जा आदि सभी का उपयोग स्थानीय उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा और देश में अनेक उपलब्ध संसाधन हैं जिनसे पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। सौर ऊर्जा से अनेक उपकरण चलाये जा सकते हैं व घर में प्रकाश करने की आवश्यकता हो, खेत में फसल उत्पाद सुखाने की आवश्यकता हो, ठन्डे प्रदेशों में पानी गर्म करने की आवश्यकता हो इत्यादि देश में पशुधन पर्याप्त है उनसे मिलने वाले गोबर एवं कृषि से बचे हुए अनुपयोगी उत्पाद और घरों से भी निकले हुए कचरे से बड़ी मात्रा में बायोगैस बनाई जा सकती है। इसको सीधे भी उपयोग कर सकते हैं या फिर स्वच्छ करके सिलिंडर में भरके, कोई भी वाहन आदि चलाया जा सकता है इस तरह से बनने वाली गैस वे सभी काम कर सकती हैं जो एल.पी.जी. या सी.एन.जी. कर सकती हैं। इस तरह से गाँव में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को कम से कम किया जा सकता है।

जैविक खेती -कार्बनिक खेती की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं

- कार्बनिक पदार्थ के स्तर को बनाए रखने, मिट्टी जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और सावधानीपूर्वक यांत्रिक हस्तक्षेप को बनाए रखने से मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता की रक्षा करना

- अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत अद्युलनशील पोषक खोतों का उपयोग करके फसल पोषक तत्व प्रदान करना जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा संयंत्र में उपलब्ध कराए जाते हैं।
- फलियां और जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के उपयोग के माध्यम से नाइट्रोजन आत्म-पर्याप्तता, साथ ही फसल अवशेषों और पशुधन खाद सहित कार्बनिक पदार्थों के प्रभावी रीसाइकिलिंग।
- खरपतवार, बीमारी और कीट नियंत्रण मुख्य रूप से फसल रोटेशन, प्राकृतिक शिकारियों, विविधता, जैविक खाद, प्रतिरोधी किरणों और सीमित (अधिमानतः न्यूनतम) थर्मल, जैविक और रासायनिक हस्तक्षेप पर निर्भर है
- पशुधन का व्यापक प्रबंधन, पोषण, आवास, रखाख्य, प्रजनन और पालन के संबंध में उनके विकासवादी अनुकूलन, व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं और पशु कल्याण के मुद्दों के प्रति पूर्ण सम्मान का भुगतान करना।

हम इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गाँवों के पर्यावरण-अनुकूल तकनीकी समाधान देने में इस परियोजना के माध्यम से भारत सरकार की पहल का हिस्सा बनकर खुश हैं जिससे समाज के मानव संसाधनों की मूल आजीविका को समृद्ध किया जा सके। इस अभियान के तहत कॉलेज गाँव के पंचायतों के साथ मिलकर काम करेगा और स्थानीय ग्रामीणों के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करने के नियमित अभ्यास में भारत सरकार के दृष्टिकोण को फैलायेगा।

उन्होंने बताया कि चयन करने और ग्राम पंचायतों और आस-पास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध में काम करने के अवसर प्रदान करने के लिए एचएचआरडी का धन्यवाद किया। कॉलेज आईआईटी दिल्ली से परामर्श लेगा और पास के गाँवों को समाधान और समर्थन प्रदान करने के लिए मथुरा के स्थानीय सरकारी अधिकारियों से भी मार्गदर्शन लेगा।

इस अवसर पर संस्थान के समस्त डीन, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की।

एच.पी.राजपूत
मीडिया प्रभारी